भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 586 का उत्तर

धौलपुर-सरमथुरा रेल परियोजना

586. श्री भजन लाल जाटव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धौलपुर-सरमथुरा रेल परियोजना की घोषणा वर्ष 2022-23 में किए जाने के बावजूद इसके दूसरे चरण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि उक्त परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और बजट आवंटन प्रक्रियाओं में काफी विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि यह परियोजना वर्ष 2025 के दौरान शुरू हो जाएगी जिससे करौली-धौलपुर क्षेत्र में लाखों लोगों को बेहतर रेल संपर्क की सुविधा मिल सकेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): गंगापुर सिटी तक नई लाइन का विस्तार (144.6 कि.मी.) के साथ धौलपुर-सरमथुरा आमान परिवर्तन परियोजना एक स्वीकृत परियोजना है। इस कार्य को दो चरणों में निष्पादित करने की योजना बनाई गई है।

चरण-I

धौलपुर-सरमथुरा आमान परिवर्तन (69.1 कि.मी.) का कार्य शुरू किया गया है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 246 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। उपलब्ध भूमि पर कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। मार्च, 2025 तक इस परियोजना पर 287 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस परियोजना हेतु 240 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

चरण-II

सरमथुरा - गंगापुर (करौली के रास्ते) (76 कि.मी.) के बीच नई रेल लाइन के लिए, फील्ड सर्वेक्षण कार्य और विस्तृत अनुमान का कार्य शुरू किया गया है।

रेल परियोजनाओं त्वरित अनुमोदन और क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) निधि की पर्याप्त उपलब्धता, (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iii) विविध स्तर पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी, और (iv) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन एवं वन्यजीव संबंधी स्वीकृति और योजना से संबंधित अन्य मामलों का समाधान हेतु राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों से नियमित वार्ता आदि शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014 से कमीशनिंग की दर में काफी वृद्धि हुई है।

किसी भी रेल परियोजनाओं का पूरा होना निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती हैं जिसमें निम्नभलिखित शामिल हैं:-

- **भूमि अधिग्रहण**
- **वन संबंधी स्वीकृति**
- **अतिलंघनकारी साधनों का स्थानांतरण**
- **विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां**
- **क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति**
- **परियोजना विशेष स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि**

ये सभी कारक परियोजना/ओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

*****